

परिणामी बजट वर्ष 2022-23

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2022-23	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार एवं विकास हेतु भिलाई में स्थापित किया गया है।	651	भिलाई नगर निगम को मंगल भवन के मासिक किराये का भुगतान किया जाता है।	
2	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	एस.टी.पी.आई. के साथ एन.आई.टी रायपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	20000	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप एवं स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम में योगदान हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई.) की स्थापना	
3	मुख्यमंत्री ई-समीक्षा	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	20000	<ol style="list-style-type: none"> 1. सीएम डैशबोर्ड राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने में मदद । 2. सीएम सचिवालय में एक केंद्रीकृत निगरानी उपकरण 3. सीएम सचिवालय स्तर पर पहलों की निगरानी और मूल्यांकन में सहायता 	
4	बिल्डनेक्स्ट परियोजना	शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों का वेबसाइट का डिजाइन, संचालन एवं एप्लीकेशन निर्माण करना तथा इसके लिये इन-हाऊस मैनुपावर की भर्ती किया जाना	27900	विभिन्न विभागों की सेवाओं, मुख्यमंत्री फ्लैगशीप योजनाओं, लोक सेवा गारंटी आदि योजनाओं के लिए पोर्टल एवं एप्स बनाने हेतु	
5	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	250000	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	
6	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यों में डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	25000		

परिणामी बजट वर्ष 2022-23

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2022-23	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
7	ई-जिला परियोजना	ई-जिला परियोजना की विविध आवश्यकताओं के लिए	56100	डिजिटल सचिवालय 1.0 एप्लीकेशन का सम्पूर्ण पुननिर्माण नवीन क्लाउड एनाबल माइक्रो सर्विस तकनीक में करते हुए डिजिटल सचिवालय 2.0 के अ.ए.एफ.पी. में अंकित सभी मॉड्यूलों का विकास एवं क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाना है।	
8	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	नवीनतम प्राइवेट क्लाउड वेस्ट डेटा सेंटर की स्थापना	270000	संचालन एवं रखरखाव, हार्डवेयर एवं सर्वर लाइसेंस के लिए, एस.एम.एस. सेवा, मानव संसाधन, नए एस.आई. का भुगतान (ऑनबोर्ड करने के लिए), नई सेवाओं और अन्य विविध आवश्यकताओं की जानकारी के लिए	
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान	नेशनल ई-गवर्नेंस आशिक्षण - शासकीय सेवकों को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में संबंधित आशिक्षण देना	2000	विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हेतु स्टेट डेटा सेंटर में अत्याधुनिक नवीनतम क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना कर विभागों के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं डेटा को सुरक्षित होसिंग प्रदान करना। वर्तमान स्टेट डाटा सेंटर में लगभग 175 से अधिक वेबसाइट एवं एप्लीकेशन होस्टेड है।	
10	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना	ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं कुशल बनाना	25000	छत्तीसगढ़ आशासन अकादमी में आशिक्षण कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाना एवं प्रत्येक कमरे में कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं कम्प्यूटर लैब स्थापना हेतु।	
				विभिन्न विभागों तथा उनकी एजेंसियों को निविदा कार्य हेतु ऑनलाईन सुविधा	

परिणामी बजट वर्ष 2022-23

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2022-23	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
11	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थापना करना, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर, तकनीकी संवर्धन, प्रतिभा पलायन को रोकने में सहायता एवं उद्यमिता और इनोवेशन हेतु प्रोत्साहन होगा	20000	100 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप की स्थापना एवं स्टार्टअप के माध्यम से 700 से अधिक रोजगार सृजन	
12	छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स परियोजना	राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक सूचनाओं को केन्द्रीयकृत कर विभागों को प्रबंधन कार्य हेतु जिओ इन्फॉर्मेटिक्स/जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य के शासकीय विभागों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराना।	10000	केन्द्रीयकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सर्विसेस राज्य के शासकीय विभागों हेतु विकसित/प्रदान किया जाएगा।	
13	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	28000	28 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी एवं 4 नवीन जिलों में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का स्थापना एवं संचालन	
15	स्टेट पोर्टल परियोजना	शासन के नवीन पोर्टल का रोलआउट एवं क्रियान्वयन करना	15000	राज्य के समस्त विभागों का वेबसाइट का अपडेशन एवं रखरखाव	
16	छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	स्थापना मद अंतर्गत कार्यालयीन व्यय आदि का रखरखाव एवं संधारण	115000	चिप्स हेतु स्थायी कार्यालय की स्थापना, जो स्मार्ट सिटी के आई.टी की आवश्यकता में महत्वपूर्ण है।	
17	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	4600	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	
18	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	110000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं रोजगार करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	
19	मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष भवनों में वाई-फाई सुविधा की स्थापना	मंत्रालय भवन और विभागाध्यक्ष भवन में वाई-फाई इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, संचालन एवं	25000		

परिणामी बजट वर्ष 2022-23

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2022-23	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		रख-रखाव हेतु		इस परियोजना हेतु हाल के दिनों में ही चिप्स को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है।	
20	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	विश्व बैंक की सहायता से पब्लिक वित्त के प्रबंधन में अकाउन्टीबिलिटी में सुधार, राजस्व प्रशासन को मजबूत करना एवं चयनित योजनाओं के लाभ हेतु वितरण की दक्षता में सुधार करना।	205000	योजना के अंतर्गत एकीकृत सक्रिय ई-शासन प्रणाली प्रदान करना।	
21	संचार क्रांति योजना	राज्य में मोबाईल नेटवर्क का विस्तार एवं मोबाईल के उपयोग को बढ़ावा देना	1088700	मोबाइल वितरण और सेवाओं के लिए कॉन्ट्रैक्टर का भुगतान	
22	भारत नेट परियोजना	राज्य में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क का विस्तार करना	150000	ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना	